

चरण सिंह @चरणजीत सिंह

बनाम।

उत्तरखंड राज्य

(2012 की आपराधिक अपील संख्या 447) 20 अप्रैल, 2023

[न्यायमूर्तिगण अभय एस. ओका और राजेश बिंदल]

दंड संहिता, 1860:धारा 304 बी, 498 ए और 201-दहेज मृत्यु-दहेज मृत्यु के रूप में अनुमान-अभियोजन मामला कि महिला ने दो साल पहले शादी की थी, उसकी पति-अपीलार्थी और ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी-मृत्यु अप्राकृतिक थी और पीड़ित का अंतिम संस्कार उसके माता-पिता को बताए बिना किया गया था-निचली न्यायालय ने अपीलार्थी, बहनोई और सास को दोषी ठहराया। 304 बी, 498 ए और 201 ने उन्हें धारा 304 बी के तहत दस साल के लिए सश्रम कारावास, क्रमशः दो साल के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 498 ए और 201-अपील में, बहनोई और सास की दोषसिद्धि और सजा को अपास्त करना दिया गया, जबकि अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया, हालांकि, सजा यू/एस। 304 बी को घटाकर सात वर्ष कर दिया गया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:अभियोजन पक्ष के नेतृत्व वाले साक्ष्य में, किसी भी गवाह ने अपीलार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा मृत्यु से तुरंत पहले या अन्यथा दहेज की मांग के कारण पीड़ित के साथ क्रूरता या उत्पीड़न के बारे में नहीं कहा-बल्कि किसी द्वारा उत्पीड़न का वर्णन नहीं किया गया-मोटरसाइकिल और भूमि की मांग के बारे में केवल कुछ मौखिक कथन जो घटना से बहुत पहले भी थे-अभियोजन पक्ष के नेतृत्व वाले साक्ष्य ने यू/एस का अनुमान लगाने के लिए पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। 304 बी या एस। 113 साक्ष्य अधिनियम का बी-यहां तक कि एस के तत्व भी। 498 ए नहीं बनाया गया-विवाह के सात वर्षों के भीतर वैवाहिक घर में पीड़ित की अप्राकृतिक मृत्यु अभियुक्त यू/एस. एस. को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। 304 बी और 498 ए-मृत्यु का कारण जैसा कि ज्ञात नहीं है-इस प्रकार, अपीलार्थी का दोषसिद्धि और सजा यू/एस. एस. 304 बी, 498 ए और 201 न्यायोचित नहीं-उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को अपास्त करना दिया गया-साक्ष्य अधिनियम -एस. 113

बैजनाथ बनाम एमपी राज्य (2017) 1 एससीसी 101:[2016] 11 एस. सी. आर. 764-संदर्भित।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार -2012 की आपराधिक अपील संख्या 447।

2001 के सी. आर. एल. ए. सं. 387 और 1997 के 1667 में नैनीताल में उत्तरांचल उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से। शुभांशु पाधी, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

जतिंदर कुमार भाटिया, कृष्णम मिश्रा, परम कुमार मिश्रा, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय राजेश बिंदल, जे द्वारा दिया गया था।

1. अपीलार्थी, जो मृतक का पति था, ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, आई. पी. सी.) की धारा 304 बी, 498 ए और 201 के तहत अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील दायर की है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 304 बी के तहत 10 साल, धारा 498 ए के तहत 2 साल और आईपीसी की धारा 201 के तहत 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। हालाँकि, नैनीताल में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत अपीलार्थी की सजा को दस साल से घटाकर सात साल कर दिया था।

2. अपीलार्थी और मृतक छीलो कौर की शादी वर्ष 1993 में हुई थी। मृतका अपने ससुराल में रहती थी। मृतक के पिता प्रताप सिंह (पीडब्ल्यू-1) ने पी. एस. जसपुर में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी छीलो कौर की शादी लगभग दो साल पहले अपीलार्थी से हुई थी। शादी में, उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पर्याप्त दहेज दिया था। शादी के दो महीने बाद, उसकी बेटी अपने माता-पिता के घर आई और शिकायतकर्ता (पीडब्ल्यू-1) को बताया कि उसके ससुराल वाले उसे मोटरसाइकिल लाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि मोटरसाइकिल दहेज में नहीं दी गई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी को यह कहते हुए शांत किया कि वर्तमान में वह मोटरसाइकिल देने में सक्षम नहीं है, हालांकि, जब भी वह ऐसा करने की स्थिति में होगा, तो वह निश्चित रूप से मोटरसाइकिल दे देगा और ऐसा कहकर उसने अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दिया। इसके बाद, जब भी उसकी बेटी माता-पिता के घर आती थी, तो वह मोटरसाइकिल की मांग के बारे में बात करती थी और शादी के लगभग एक साल बाद जमीन की मांग भी की गई थी। हर बार वह अपनी बेटी को शांत करता था।

और उसे वापस भेज दिया। पिछले दिन यानी आईडी1 पर गाँव भोगपुर बांध का जागीर सिंह, जहाँ उसकी बेटी अपीलार्थी के साथ शादी के बाद रहती थी, शिकायतकर्ता के पास आया और उसे बताया कि उसकी बेटी, छीलो कौर की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। सूचना मिलने पर शिकायतकर्ता अपनी पत्नी के साथ गाँव भोगपुर बांध पर आई और यह जानकर हैरान रह गई कि सुबह लगभग 8 बजे उसकी बेटी को उसके पति चरण सिंह (यहाँ अपीलार्थी), बहनोई गुरमीत सिंह (आरोपी संख्या 2) और सास सैंटो कौर (आरोपी संख्या 3) ने पीटा और गला दबाकर मार डाला। यहाँ तक कि उन्होंने वादी को सूचित किए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मोटरबाइक और दहेज में जमीन की मांग को पूरा न करने के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच की गई और चरण सिंह, गुरमीत सिंह और सैंटो कौर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। 3. अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों से पूछताछ की और बचाव पक्ष ने एक गवाह से पूछताछ की। विचारण न्यायालय ने सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद चरण सिंह (अपीलार्थी), गुरमीत सिंह और सैंटो कौर को आई. पी. सी. की धारा 304 बी, 498 ए और 201 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत दस साल के सश्रम कारावास, आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत दो साल के सश्रम कारावास और आई. पी. सी. की धारा 201 के तहत दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषियों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील में, गुरमीत सिंह (बहनोई) और सैंटो कौर (सास) की आईपीसी की धारा 304 बी, 498 ए और 201 के तहत दोषसिद्धि और सजा को अपास्त करना दिया गया और उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया। हालांकि, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत दस साल के सश्रम कारावास की सजा को घटाकर सात साल कर दिया गया था। यह उच्च न्यायालय का पूर्वोक्त निर्णय है जिसे वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है।

4. श्री शुभ्रांशु पाधी, विद्वान अधिवक्ता, जिनसे अपील दायर करने वाले वकील की अनुपस्थिति के कारण न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया गया था, ने कहा कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को आई. पी. सी. की धारा 304 बी या 498 ए के तहत कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है। आई. पी. सी. की धारा 304 बी के तहत अनुमान लगाने के लिए पूर्व-आवश्यकता यह है कि मृत्यु से तुरंत पहले, मृतक को दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। दहेज मृत्यु के संबंध में उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में, 'आईईए') की धारा 113 बी के संदर्भ में केवल तभी की जा सकती है जब यह दिखाया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उस महिला को दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

5. यदि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की जांच की जाती है, तो आई. पी. सी. की धारा 304 बी या 498 ए के तहत दोषसिद्धि का कोई मामला संभवतः नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि मृतक की मृत्यु से तुरंत पहले उसका कोई उत्पीड़न या क्रूरता या दहेज की मांग की गई थी। शादी वर्ष 1993 में हुई थी, मृतक की मृत्यु 22.6.1995 को हुई थी। मृतक के पिता, नानी या मामा सहित उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में उसके उत्पीड़न के बारे में कुछ नहीं कहा है। वास्तव में, मृतक के गांव से लगभग एक फ़र्लांग की दूरी पर रहने वाली नानी और दो मामा भी मृतक के अंतिम संस्कार के समय मौजूद थे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर या किसी अन्य तरीके से कोई मुद्दा नहीं उठाया। वास्तव में, मृतक की नानी और मामाओं ने यह स्वीकार किया कि दाह संस्कार के बाद, पंचायत के हस्तक्षेप से, उन्होंने दहेज में दिए गए सभी सभी सामान एकत्र किये थे। आगे यह बताया गया कि मृतक के पिता को भी सूचना दी गई थी जो वास्तव में लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। हालांकि, मृतक के पिता के आने का इंतजार करने के कारण अंतिम संस्कार में विलम्ब नहीं किया जा सकता था।

6. यह आगे तर्क दिया गया कि एक महत्वपूर्ण गवाह, जागीर सिंह, जिसे शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी में नामित किया था, को अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत में पेश नहीं किया गया है। वह वह व्यक्ति है जो शिकायतकर्ता के अनुसार भोगपुर डैम गांव का निवासी है, जहां मृतक अपने ससुराल वाले घर में रहती थी। उन्होंने वादी को उनकी बेटी की मौत के बारे में सूचित किया था। अभियोजन पक्ष ने इस महत्वपूर्ण साक्षी को क्यों रोक रखा था? जांच अधिकारी बब्बन सिंह, जो पी डब्ल्यू-6 के रूप में परीक्षित हुए हैं, के बयान के अनुसार, जांच के दौरान जागीर सिंह का बयान दर्ज किया गया था। एक बार जब भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी, 498-ए और आईईए की धारा 113-बी के अवयव साबित नहीं बनते हैं, तो दहेज मृत्यु की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है। तर्कों के समर्थन में, बैजनाथ बनाम एम. पी. 1 राज्य पर निर्भरता रखी गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी, उसके भाई और मां के खिलाफ लगाए गए आरोप समान थे। हालांकि, उसके भाई और मां की दोषमुक्ति के खिलाफ, राज्य द्वारा कोई अपील नहीं की गई है और अपीलकर्ता की पत्नी की मृत्यु अप्राकृतिक नहीं थी क्योंकि उसे दौरे पड़ते थे। अपनी जिरह में, नानी ने स्वीकार किया कि मृतक को बुखार आया था।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक युवती की उसके ससुराल वालों ने दहेज की लालसा में हत्या कर दी थी। विवाह को मात्र दो वर्ष हुए थे और मृत्यु अप्राकृतिक थी। मृतक का अंतिम संस्कार उसके माता-पिता को सूचित किए बिना कर दिया गया। दाह संस्कार के समय मौजूद नानी और उसके दो मामाओं ने मृतक के शरीर पर चोट के निशान और टूटे हुए दांत भी देखे थे। वे शिकायत इसलिए दर्ज नहीं करा सके क्योंकि उनको धमकी मिली थी। मृत्यु ससुराल में हुई, इसलिए उपधारणा का खंडन करने का महती भार अपीलार्थी पर है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयानों के रूप में अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है कि अपीलार्थी द्वारा बार-बार दहेज की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत अपीलार्थी

के दंड को दस साल कारावास से सात साल करके, जोकि इस धारा के तहत दी जाने वाली कम से कम सजा है, पहले से ही पर्याप्त अनुग्रह कर दिया गया है।

8. पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना और प्रासंगिक रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

9. मृतका के साथ अपीलार्थी का विवाह वर्ष 1993 में संपन्न हुआ था। 22.6.1995 को उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के पिता की शिकायत पर 24.6.1995 पर चरण सिंह, अपीलार्थी, बहनोई, गुरमीत सिंह और सास सैंटो कौर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय में दोषियों द्वारा दायर अपील में, बहनोई गुरमीत सिंह और सास सैंटो कौर को बरी कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत अपीलार्थी को दी गई सजा को दस साल के सश्रम कारावास से घटाकर सात साल के सश्रम कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। आईपीसी की धारा 498 ए और धारा 201 के तहत दी गई दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा की पुष्टि की गई थी। 10. अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 304 बी और 498 ए के तहत दोषी ठहराया गया है, जिसमें शादी के सात साल के भीतर दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान लगाया गया है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों के सही अनुशीलन के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, 498 ए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी का अवलोकन किया जाना चाहिए। इन्हें नीचे निकाला गया है:-

“304 बी -दहेज मृत्यु-— (1) जहाँ किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

जो कोई भी दहेज मृत्यु कारित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

498-A. किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार

उसे क्रूरता के अधीन करना-जो कोई भी, किसी महिला के पति या पति का रिश्तेदार होने के नाते, ऐसी महिला को क्रूरता के अधीन करता है, उसे तीन साल तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" का अर्थ है -

((क) ऐसा कोई जानबूझकर किया गया आचरण जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है या जिससे महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा हो सकता है; या

(ख) उस स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना जहां तंग करने का उद्देश्य उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए प्रपीड़ित करना है या ऐसी मांग को पूरा करने में वह या उससे संबंधित कोई व्यक्ति असफल रहा है।

113 बी -दहेज-मृत्यु के बारे में उपधारणा— जब सवाल आता है

यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु का कारण बना था।

स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304-बी में है।

11. बैजनाथ के मामले (ऊपर) में आई. पी. सी. की धारा 304 बी और 498 ए की व्याख्या पर विचार किया गया। इस राय का सारांश उस निर्णय के पैरा 25 से 27 में दिया गया, जो नीचे उद्धृत किया गया है:-

25. जबकि संहिता की धारा **304-ख** द्वारा परिभाषित दहेज-मृत्यु के अपराध में, उसके अवयव इस प्रकार हैं:

((i) संबंधित महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई है; और

((ii) अपनी शादी के सात साल के भीतर है, और

((iii) कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले, उसे उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

संहिता की धारा **498-क** के अधीन अपराध का आरोप महिला के पति या उसके नातेदार पर तब लगाया जाता है यदि उस महिला के साथ क्रूरता की गई है। इस धारा के अंतर्गत 'क्रूरता' को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है:

((i) ऐसा कोई जानबूझकर किया गया आचरण जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है या जिससे जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा हो सकता है, या

((ii) महिला का उत्पीड़न, जहां इस तरह का उत्पीड़न उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से है या उसकी या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण है।

इस प्रकार, दहेज की मांग या उसके संबंध में किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में महिला का उसके पति या उसके नातेदार द्वारा क्रूरता या प्रपीड़न दोनों अपराधों का समान घटक है।

27. "दहेज" शब्द का वही अर्थ है जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में है।"" "क्रूरता" "अभिव्यक्ति में, जैसा कि वर्णित किया गया है, उत्पीड़क के आचरण के अलावा, जिस स्त्री के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार किया गया है, उस क्रूरता के परिणाम भी शामिल हैं। चाहे जो भी हो, क्रूरता या दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा उत्पीड़न, दोहराने के लिए, दोनों अपराधों की गंभीरता है।

12. जैसा कि उपरोक्त मामला भी दहेज मृत्यु से संबंधित था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत उपधारणा पर भी उपरोक्त निर्णय के पैरा 29 से 31 में विस्तार से चर्चा की गई थी।उसी को नीचे निकाला गया है:-

29. उल्लेखनीय रूप से यह उपधारणा भी अपराध से आरोपित व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में मृत महिला के साथ क्रूरता या उत्पीड़न के सबूत पर आधारित है। इस प्रकार दहेज-मृत्यु के बारे में उपधारणा केवल इस तथ्य के सबूत पर सक्रिय हो जाएगी कि मृतक महिला को अभियुक्त द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था और वह भी मृत्यु की तर्कसंगत सन्निकटता में। इस प्रकार ऐसा सबूत विधायी रूप से अधिदेशित पूर्व अपेक्षा है जो अन्यथा कानूनी रूप से अधिनियमित उपधारणा का आह्वान करता है कि दहेज-मृत्यु का अपराध उससे आरोपित व्यक्ति द्वारा किया गया है।

30. इन तीनों उपबंधों का संयुक्त पठन इस प्रकार अभियोजन पर यह भार निर्दिष्ट करता है कि अभियुक्त के विरुद्ध अधिनियम की धारा 113-ख में अंतःस्थापित उपधारणा का लाभ उठाने के लिए अभियोजन को प्रत्यक्ष और विश्वासोत्पादक साक्ष्य द्वारा दोनों अपराधों के घटकों को अकाट्य रूप से सिद्ध करना होगा। इस प्रकार कानूनी उपधारणा को साबित करने के लिए अथवा उसके दायरे के भीतर आरोपित व्यक्ति को लेने के लिए पति या उसके नातेदार या आरोपित व्यक्ति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सबूत अनिवार्य है। यदि अभियोजन इस तरह के

तथ्य को साबित करने के लिए ठोस, सुसंगत और प्रेरक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उपरोक्त उल्लिखित अपराधों में से किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को साक्ष्य में कमी को छिपाने के लिए केवल उपधारणा के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

31. वैवाहिक गृह की संरक्षित सीमाओं के भीतर जीवन के अक्सर व्यावहारिक रूप से दुर्गम अवकाशों के प्रमाण की कठोरता के अभियोजन को राहत देने और आरोपित व्यक्ति के खिलाफ एक धारणा के अनुसार परिणामी शून्य को फिर से भरने की विधायी प्रधानता, शामिल धाराओं में गिने गए बुनियादी तथ्यों को विश्वसनीय रूप से साबित करने में इसकी विफलता को छिपाने और क्षमा करने के लिए अतिरंजित नहीं किया जा सकता है, ऐसा न हो कि न्याय हताहत हो।

विचाराधीन उपधारणा के संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख के संयुक्त पठन के संबंध में उक्त निर्णय के पैरा 32 में चर्चा की गई थी, जो नीचे उद्धृत की गई है:- “32. इस न्यायालय ने अक्सर संहिता की धारा 304-बी और अधिनियम की धारा 113-बी के दायरे और उद्देश्य पर विचार करते हुए कहा है कि यह धारणा इस तथ्य पर निर्भर करती है कि अभियोजन पक्ष पहले धारा के अपराध के तत्वों को स्पष्ट करता है।

304-बी जैसा कि शिंडो बनाम पंजाब राज्य में [शिंडो बनाम पंजाब राज्य] पंजाब, (2011) 11 एससीसी 517:(2011) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 394 और प्रतिध्वनित

राजीव कुमार बनाम हरियाणा राज्य में हरियाणा का, (2013) 16 एस. सी. सी. 640: (2014) 6 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 346]बाद के फैसले में, इस न्यायालय ने प्रस्ताव दिया कि संहिता की धारा 304-बी के तहत दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि अभियुक्त ने महिला की मृत्यु से तुरंत पहले दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता का शिकार होना चाहिए और इस घटक को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित करना होगा और तभी न्यायालय यह मान लेगा कि अभियुक्त ने अधिनियम की धारा 113-बी के तहत दहेज मृत्यु का अपराध किया है। इसने अनुमोदन के साथ, पहले के निर्णय का उल्लेख किया

प्रेमा एस. राव बनाम यादला श्रीनिवास राव, (2003) 1 एससीसी 217:2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 271] इस प्रभाव से कि संहिता की धारा 304-बी के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, अपराध के मुख्य घटकों में से एक जो स्थापित किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले" उसे "दहेज की मांग के संबंध में" क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था।

14. ऊपर उल्लिखित कानूनी स्थिति के संदर्भ में, मामले की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या मामला उस श्रेणी में आता है जिसमें अभियोजन पक्ष को अपना मामला साबित करने से राहत देते हुए और अभियुक्त/अपीलार्थी पर जिम्मेदारी डालते हुए अपीलार्थी के खिलाफ अनुमान लगाया जा सकता है।

15. मृतक की मृत्यु की तारीख 22.6.1995 है।उसी दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। अपीलार्थी द्वारा लिया गया रुख यह था कि मृतक के माता-पिता को सूचित किया गया था जो लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे थे। लेकिन वे समय पर नहीं पहुंच सके।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि मातृ दादी और दो मामा जो मृतक के वैवाहिक निवास से लगभग एक फरलॉंग की दूरी पर रह रहे थे, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उस समय मौजूद थे।

।उन्होंने न तो कोई मुद्दा उठाया और न ही पुलिस को सूचित किया।बल्कि पंचायत के हस्तक्षेप पर उन्होंने दहेज की सारी चीजें ले ली थीं।

16. क्रूरता या प्रपीड़न मृत्यु से ठीक पहले होना चाहिए।अपने साक्ष्य में, मृतक के पिता प्रताप सिंह (अभि. सा. -1) ने कहा कि शादी के दो महीने बाद उनकी बेटी यह कहते हुए माता-पिता के घर आई कि अपीलार्थी मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था, हालांकि, उसे वापस भेज दिया गया।इसके बाद, वह फिर से आई और उसने उसे अवगत कराया कि अपीलार्थी मोटरसाइकिल लाने के लिए उस पर दबाव डाल रहा है। मोटरसाइकिल के अलावा जमीन की भी मांग की गई। बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मृत्यु से ठीक पहले ऐसी कोई मांग की गई थी क्योंकि जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, वे काफी पुरानी हैं।उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि अंतिम संस्कार के समय उसकी सास और दो साले (पत्नी के भाई) मौजूद थे।हालांकि, उन्हें शिकायत दर्ज नहीं करवाने की धमकी दी गई।मृतका के मामा बलबीर सिंह (अभि. सा.-2) ने केवल यह कहा कि विवाह के समय मृतक के पिता द्वारा पर्याप्त दहेज दिया गया था।हालांकि, बाद में उसने सुना कि अपीलार्थी ने मोटरसाइकिल की मांग की थी।अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने स्वीकार किया कि वह अपीलार्थी के घर से लगभग एक फरलांग की दूरी पर रहता था | मृतक की शादी के समय कोई दहेज नहीं मांगा गया था।उसने यह नहीं कहा कि मृतका ने कभी भी दहेज की मांग या ऐसी मांग पूरी न होने के कारण किसी उत्पीड़न के बारे में उसे कभी कुछ बताया हो, हालांकि वह मृतक के वैवाहिक घर के करीब रह रहा था।

17. मृतक की नानी बीरो बाई (पीडब्लू-3) ने कहा कि उनका घर अपीलार्थी के घर से लगभग एक मील की दूरी पर स्थित है।वह मृतका के घर जाती थी।मृतका के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था।उसे अपने मायके (माता-पिता के घर) जाने की अनुमति नहीं थी।मृतक ने उसे सूचित किया कि अपीलार्थी उसे अपनी नानी से मोटरसाइकिल लाने के लिए कहता था। फरवरी 1995 में उसके पति की मृत्यु के बाद, अपीलार्थी ने मृतका को अपनी नानी से भूमि लेने के लिए कहा। जब उससे भूमि की मांग की गई तो उसने नकारात्मक उत्तर दिया।हालांकि, प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि उससे जमीन की मांग नहीं की गई थी।यहां तक कि उसके बयान में भी इस आशय का कोई सुझाव नहीं है कि मृत्यु से कुछ समय पहले, मृतक के साथ या तो अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कोई क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। जो कुछ भी कहा गया है वह मांग के बारे में है।किसी भी क्रूरता या उत्पीड़न का कोई विवरण नहीं है, हालांकि यह गवाह मृतक के घर से लगभग एक किलोमीटर दूर रहती था और उसकी नानी है।

जोगिंदर सिंह (अभि. सा. -4) अभियोजन द्वारा पेश किया गया एक अन्य गवाह है, जो मृतका का मामा है। उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

19. राजिन्द्र सिंह (अभि. सा.-5), उपनिरीक्षक एक औपचारिक गवाह था जिसने केवल प्राथमिकी दर्ज की थी और आरोपी को गिरफ्तार किया था।

20. बब्बन सिंह (पीडब्ल्यू-6), सर्कल ऑफिसर, फरीदपुर जांच अधिकारी थे। अपनी मुख्य परीक्षा में उसने स्वीकार किया कि उसने जगीर सिंह का बयान दर्ज किया था। वह वह व्यक्ति है जिसने पुलिस में की गई शिकायत के अनुसार, मृतका के पिता को उसकी बेटी की मृत्यु के बारे में सूचित किया था। हालांकि, उसे साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया।

21. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पूर्वोक्त साक्ष्य में, किसी भी गवाह ने अपीलार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा मृत्यु से पहले या अन्यथा दहेज की मांग के कारण मृतका के साथ क्रूरता या उत्पीड़न के बारे में नहीं बताया। बल्कि उत्पीड़न की बात भी किसी ने नहीं कही है। मोटरसाइकिल और भूमि की मांग के बारे में केवल कुछ मौखिक कथन हैं जो घटना से बहुत पहले के हैं। अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में उपरोक्त साक्ष्य आई. पी. सी. की धारा 304 बी या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत अनुमान लगाने के लिए पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। यहां तक कि आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तत्व भी उसी कारण से नहीं बनाए गए हैं क्योंकि मृतक की मृत्यु से तुरंत पहले क्रूरता और उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं है।

22. बचाव पक्ष ने गुरमेज सिंह को बचाव साक्षी -1 के रूप में पेश किया था, जो घटना के समय गांव के प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि मृतक के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को मौत की जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि मृतका का सामान दाह संस्कार के बाद उसकी नानी और मामा को सौंप दिया गया था। उनका बयान मृतका की नानी बीरो बाई (अभि. सा. -3) और बलबीर सिंह (अभि. सा. -2) द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के अनुरूप है। इसका अर्थ यह है कि मृतका की मृत्यु के बारे में कोई संदेह नहीं था।

23. अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की सामूहिक मूल्यांकन पर, हमारा विचार है कि आई. पी. सी. की धारा 304 बी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत अनुमान लगाने की पूर्व-आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। विवाह के सात वर्षों के भीतर वैवाहिक गृह में केवल अप्राकृतिक होने के कारण मृतक की मृत्यु नहीं होगी। आई. पी. सी. की धारा 304 बी और 498 ए के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। इस तरह मौत का कारण ज्ञात नहीं है।

उपर्युक्त कारणों से, हमारी राय में, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख, 498 क और 201 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को विधिक रूप से संवहनीय नहीं है। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)